



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 2004/माघ 11, 1925

No. 123]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 2004/MAGHA 11, 1925

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2004

का.आ. 151(अ).—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुम्बई उच्च न्यायालय में संघ सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के विरुद्ध सभी दांडिक रिट याचिकाएं, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, दांडिक निर्देश और दांडिक आवेदनों सहित सभी दांडिक मामलों का संचालन करने के प्रयोजन के लिए सर्वश्री मुर्तजा एम. खोखावाला और अवधूत मधुकर चिमालकर, अधिवक्ता को निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन तारीख 27 जनवरी, 2004 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपर लोक अभियोजक नियुक्त करती है, अर्थात् :—

- (क) सर्वश्री मुर्तजा एम. खोखावाला और अवधूत मधुकर चिमालकर, अधिवक्ता उक्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान मुम्बई उच्च न्यायालय में भारत संघ या केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के विरुद्ध उपर्युक्त निदेशित किन्हीं दांडिक मामलों में उपस्थित नहीं होंगे।
- (ख) सर्वश्री मुर्तजा एम. खोखावाला और अवधूत मधुकर चिमालकर, अधिवक्ता विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं.फा. 23(2)/2001-न्या., तारीख 14 मई, 2001 में अन्तर्विष्ट फीस के चिक्कण के अनुसार फीस के हकदार होंगे।

[फा. सं. 23(2)/2003-न्या.]

डी. आर. मीना, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

(Department of Legal Affairs)

(JUDICIAL SECTION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2004

**S.O. 151 (E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints S/Shri Murtaza M. Khokhawala and Avadhut Madhukar Chimalkar, Advocates as Additional Public Prosecutors for the purpose of conducting all criminal cases including all Criminal Writ Petitions, Criminal Appeals, Criminal Revisions, Criminal References and Criminal Applications by or against the Union of India or any Central Government Office or any Department of the Central Government, in the High Court of Judicature at Mumbai for a period of three years or until further orders, whichever is earlier with effect from the 27th January, 2004, subject to the following conditions, namely :—

- (a) that S/Shri Murtaza M. Khokhawala and Avadhut Madhukar Chimalkar, Advocates, shall not appear against the Union of India or any Central Government Office or any Department of the Central Government in any criminal cases referred to above in the High Court of Judicature at Mumbai during the said period of three years;
- (b) that S/Shri Murtaza M. Khokhawala and Avadhut Madhukar Chimalkar, Advocates, shall be entitled to the fee as per the statement of fees contained in the Office Memorandum No. F. 23(2)/2001-Judl., dated the 14th May, 2001, issued by the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs, New Delhi.

[F. No. 23(2)/2003-Judl.]

D. R. MEENA, Jt. Secy. &amp; Legal Adviser

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2004

**का.आ. 152(अ).**—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुम्बई उच्च न्यायालय में संघ सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के विरुद्ध सभी दाण्डिक रिट याचिकाएँ, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, दाण्डिक निर्देश और दाण्डिक आवेदनों सहित सभी दाण्डिक मामलों का संचालन करने के प्रयोजन के लिए श्री रियाज फकीर मोहम्मद लेम्बे, अपर लोक अभियोजक को निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन तारीख 28 अक्टूबर, 2003 से और तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाती है; अर्थात् :—

- (क) श्री रियाज फकीर मोहम्मद लेम्बे, उक्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान मुम्बई उच्च न्यायालय में भारत संघ या केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के विरुद्ध उपर्युक्त निदेशित किन्हीं दाण्डिक मामलों में उपस्थित नहीं होंगे।
- (ख) श्री रियाज फकीर मोहम्मद लेम्बे, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं.फा. 23(2)/2001-न्या., तारीख 14 मई, 2001 में अन्तर्विष्ट फीस के विवरण के अनुसार फीस के हकदार होंगे।

[फा. सं. 23(2)/2003-न्या.]

डी. आर. मीना, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2004

**S.O. 152(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby extends the term of appointment of Shri Riyaz Fakir Mohammed Lambay, Advocates as Additional Public Prosecutor for the purpose of conducting all criminal cases including all Criminal Writ Petitions, Criminal Appeals, Criminal Revisions, Criminal References and Criminal Applications by or against the Union of India or any Central Government Office or any Department of the Central Government, in the High Court of Judicature at Mumbai for a further period of three years or until further orders, whichever is earlier with effect from the 28th October, 2003 subject to the following conditions, namely :—

- (i) that Shri Riyaz Fakir Mohammed Lambay will not appear against the Union of India or any Central Government Office or any Department of the Central Government in any criminal cases referred to above in the High Court of Judicature at Mumbai during the said period of three years;
- (b) that Shri Riyaz Fakir Mohammed Lambay shall be entitled to the fee as per the statement of fees contained in the Office Memorandum No. F. 23(2)/2001-Judl., dated the 14th May, 2001, issued by the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs, New Delhi.

[F. No. 23(2)/2003-Judl.]

D. R. MEENA, Jt. Secy. &amp; Legal Adviser